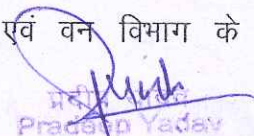


## मानक शर्ते

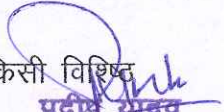
गेल इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) की 36"/24" व्यास की ( ज़ॉसी - औरैया -कूलपुर ) गैस पाईप लाईन बिछाये जाने की परियोजना के लिये तथा उनके मान्य होने का प्रमाण पत्र

(वन अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 7314/14-3-1980/82 दिनांक 31-12-2004 द्वारा निर्धारित)

1. भूमि हस्तांतरण के बाद भी उस के वैधानिक स्तर मे कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाँति चिन्हित/संरक्षित भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का प्रयोग केवल कथित प्रयोजनों हेतु ही किया जाएगा। अन्य प्रयोजनों हेतु कदापि नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाए कि माँगी गई भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. अधोहस्ताक्षरी विभाग उसके कर्मचारी अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाएंगे और ऐसा किया जाने पर सम्बंधित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
6. भूमि सीमांकन नियंत्रक विभाग अपने व्यय से सम्बंधित वनाधिकारी की देख-रेख में कराएगा तथा इस सम्बंध में बनाए गए मुनारे आदि की देख-भाल करेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरित विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाये। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ण एवं वन जन्तुओं के स्वच्छन्द विचरण कि व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जाएगी।
9. सिचाई विभाग/जल विभाग द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

  
Pradeep Yadav  
वरिष्ठ प्रबन्धक (निर्माण), लखनऊ  
Sr. Manager (Construction), Lucknow  
गेल (इंडिया) लिमिटेड  
GAIL (India) Ltd  
लखनऊ (226010)  
Lucknow (226010)


10. याचक विभाग द्वारा हस्तांतरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकार का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जाएगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतंत्र बिना किसी प्रतिकार का भुगतान किए वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जाएगा।
11. सड़क निर्माण में प्रस्तावों पर "एलाइनमेन्ट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग को परामर्श सा०नि०वि० द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता सा०नि०वि० के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र सं० सी दिनांक 10.02.82 में निहित आदेशों का पालन भी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा। अश्व मार्ग बनाना वन मार्गों को मामूली फेरबदल कर पक्का करना होगा बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बंधी प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होगा। जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उ०प्र० वन निगम अथवा अन्य उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझें द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग से सम्भव न हो सके और उसका पालन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि में पडने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षा रोपण का भुगतान अथवा एक वृक्ष के स्थान पर 10 वृक्षों का रोपण तथा 3 वर्षों तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाए का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निशिद्ध है। इसी प्रकरण बॉज के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
15. वन भूमि के उपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जाएगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है। तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जाएगी जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-रक्षण की सम्भावना होती हैं। और नहर के दोनों पटरीयों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है। तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वयं करेगा।
17. उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होंगी।

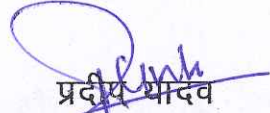
  
**Pradeep Yadav**  
 श्री प्रबन्धक (निर्माण), लखनऊ  
 Sr Manager (Construction), Lucknow  
 गैल (इंडिया) लिमिटेड  
 GAIL (India) Ltd  
 लखनऊ (226010)  
 Lucknow (226010)

18. वन विभाग का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाए जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाए अथवा उसका उचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाए


मैं गेल इण्डिया लिमिटेड का प्रतिनिधि यह प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त उल्लेखित सभी शर्तें मान्य हैं तथा उनका अनुपालन किया जाएगा।

  
प्रदीप यादव  
लखनऊ

  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
सौराँव, इलाहाबाद

  
प्रदीप यादव  
वरिष्ठ प्रबंधक (निर्माण)  
गेल इण्डिया लिमिटेड

लखनऊ  
प्रदीप यादव  
Pradeep Yadav  
वरिष्ठ प्रबंधक (निर्माण), लखनऊ  
Sr Manager (Construction), Lucknow  
गेल (इंडिया) लिमिटेड  
GAIL (India) Ltd  
लखनऊ (226010)  
Lucknow (226010)

  
प्रमाणिक निदेशक  
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग  
इलाहाबाद